सूखे का संकट

जून-जुलाई में मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका खेती के लिए चिंताजनक है. बारिश का अनुमान लगानेवाली निजी संस्था स्काईमेट ने बताया है कि अलनीनो के कारण जून में 23 और जुलाई में नौ फीसदी कम बारिश हो सकती है. इसका सबसे ज्यादा असर मध्य और पूर्वी भारत पर होगा. हालांकि, पूरे मॉनसून (जून से सितंबर तक) में बारिश औसत के 93 फीसदी तक होने का आकलन है, किंतु जून और जुलाई बहुत अहम है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई इन्हीं महीनों में होती है. अगर यह अनुमान सही होता है, तो औसत से कम बारिश का यह लगातार तीसरा साल होगा. इससे खेती पर नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही, पानी की उपलब्धता भी कम हो जायेगी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (गांधीनगर) द्वारा संचालित प्रणाली ने मार्च के आखिरी दिनों का विश्लेषण कर बताया है कि देश का 42 फीसदी जमीनी हिस्सा सूखे की चपेट में है. सबसे ज्यादा संकट आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में है. इन राज्यों में भारत की करीब 40 फीसदी आबादी रहती है. अभी तक केंद्र सरकार ने किसी भी क्षेत्र को सूखा-प्रभावित घोषित नहीं किया है, परंतु आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान की सरकारों ने कई जिलों को संकटग्रस्त श्रेणी में डाल दिया है. जानकारों का मानना है कि अभी मॉनसून में देरी है, सो आगामी तीन महीनों में इन इलाकों में हालत और गंभीर होगी. जून और जुलाई में अगर ठीक से बारिश नहीं हुई, तो संकट गहरा हो जायेगा. पिछले साल अक्तूबर से दिसंबर के बीच सामान्य से 44 फीसदी कम बरसात हुई थी. इस अवधि की बारिश पूरे साल की बारिश का 10 से 20 फीसदी होती है. पिछले मॉनसून में सामान्य से 9.4 फीसदी कम बरसात हुई थी. यदि यह कमी 10 फीसदी होती है, तब मौसम विभाग सूखे की घोषणा कर देता है. भारत को 2015 से इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. साल 2017 की अच्छी बारिश ने बड़ी राहत दी थी और खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा था, पर उसके बाद मॉनसून कमजोर पड़ता रहा है. बड़े जलाशयों में पानी क्षमता से काफी कम है. सूखे से जहां कृषि संकट बढ़ेगा, वहीं सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए भूजल का दोहन भी अधिक होगा. इसका एक नतीजा पलायन के तेज होने के रूप में भी हो सकता है, जिससे शहरों और अन्य क्षेत्रों पर दबाव बढ़ेगा. निश्चित रूप से यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होगी और इससे जूझना आगामी सरकार के लिए आसान नहीं होगा. देश के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रह चुके प्रणब मुखर्जी ने कभी कहा था कि देश का असली वित्त मंत्री मॉनसून है. भूजल, नदियों और जलाशयों के साथ जमीनी हिस्से के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत बारिश ही है. ऐसे में जरूरी है कि सरकारें और संबद्ध विभाग इस संकट का सामना करने की तैयारी तेज करें.

सूखे से जहां कृषि संकट बढ़ेगा, वहीं सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए भूजल का दोहन भी अधिक होगा. इसका एक नतीजा पलायन के तेज होने के रूप में भी हो सकता है...

ध्यान में रहे भारत का हित

मृणाल पांडे
ग्रुप सीनियर एडिटोरियल एडवाइजर, नेशनल हेराल्ड
mrinal.pande@gmail.com

बालाकोट के बाद का लगातार उन्माद से भरा चुनावी मंजर राजनेताओं के मनोविज्ञान में रुचि रखनेवालों के लिए दिलचस्प मसाला है. 'चुन-चुन के बदला लेंगे' और 'घर में घुसकर मारूंगा' वाले बयानों ने सोचे-समझे बगैर भारत और पाक ही नहीं, भारत-पाक एवं चीन, भारत-पाक एवं अमेरिका के रिश्तों के कई उत्पाती प्रेतों को आजाद कर दिया है. भारतीय राजनय के स्वरूप, पड़ोसी रिश्तों, महाशक्तियों की छुपी इच्छाओं और इरादों से गढ़ी जा रही एशियाई बिसात की रणनीतियों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है. जिस एक बात पर दो विश्वयुद्धों से झुलस चुकी दुनिया एकमत है, वह यह है कि परमाणु शक्ति वाले दो देशों के बीच युद्ध छिड़ना या तनावभरी स्थिति में भड़काऊ तरह से घी डालना विश्वभर के लिए खतरा है. इसलिए बालाकोट की आग पर ढक्कन लगाने को तुरंत सारी दुनिया हरकत में आ गयी और सेनाधिपति कगार से पीछे हट गये.

सवाल है कि ऐन चुनावी संध्या पर पाकिस्तान भला भारत की सीमा पर बार-बार हंगामा क्यों मचा रहा है? इसकी बड़ी वजह है एशिया पर एकछत्र राज्य करने के इच्छुक चीन की दीर्घकालिक नीतियां. चीन की विदेश नीति में दर्शन और खुराफात का एक अजीब मिश्रण है. उसने ताओ से माओ तक दर्शन का पारायण करके अपने अगली सदी के भूराजनीतिक लक्ष्य तय किये हैं, जिनमें भारत के खिलाफ जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को अपनी मिसाइल बनाना शामिल है. चीन ठोस खुर्राट और व्यावहारिक बनकर पाक धरती पर अपने व्यापारिक सामरिक हितों के तहत सड़कों से लेकर बंदरगाह तक बनाने के कार्यक्रम पर चुस्ती से अमल कर रहा है.

हमारा मामला उल्टा है. हमारे नेता दूरगामी फल की चिंता किये बिना फौरी चुनावी जरूरतों से ही लक्ष्य तय कर हमले पर उतारू हो जाते हैं. राष्ट्रवादी भाषणों की आग से शुरुआत होती है. यहां तक तो तब भी ठीक है. दिक्कत तब शुरू होती है, जब प्रधान सेवक ही देश के हर सूबे में पाक और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन्माद जगाते जनता को हिंसक संदेशों से उकसाते हैं. हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आज आतंकवाद के खिलाफ खुला युद्ध छेड़कर पाक से सामरिक टकराव मोल लेना चीन को हस्तक्षेप के लिए न्योतना साबित होगा. इस क्रम में हमको रूस के पारंपरिक समर्थन की आस भी नहीं पालनी चाहिए. हम नहीं मान सकते कि चीन के बूते पाक अगर हम पर हमलावर हुआ, तो उसके खिलाफ हमको ट्रंप का नस्लवादी, संकुचित घरेलू स्वार्थों का रक्षक बनता जा रहा अमेरिका रक्षा की गारंटी देगा. उसके खुद अपने खरबों डॉलर चीन में निवेशित हैं.

आज युद्धोन्मादी राष्ट्रवाद सरकार की घरेलू और वैदेशिक नीतियों की असफलता पर पर्दा डालने के हिंदुत्व की परंपरा के रक्षण का हिस्साभर है. बार-बार वही सतयुग-द्वापर युग के मुहावरों में सौ साल लड़ने, सर काट लाने, एक के बदले सवा सौ मारने की बातें बेरोजगारी, कृषि की बदहाली और छीजते पर्यावरण की ठोस सच्चाइयों से घिरे देश को न सिर्फ उबाती हैं, बल्कि उसकी उल्टी प्रतिक्रिया भी संभव है. हमको अगले सौ-पचास सालों में तरक्की करनी है. इसके लिए विश्वविमुख बड़बोले आलसियों की जमात से बाहर आकर भारत की चिंताजनक सामाजिक आर्थिक सचाइयों पर जारी उन ठोस आंकड़ों का सच हमको स्वीकार करना होगा, जिनको हमारे अनुभवसंपन्न राष्ट्रीय शोध संस्थान सामने ला रहे हैं.

जनसंपर्क और आत्म-प्रचार को हमारे नेतृत्व ने शुरुआती काल में चाहे जितना भी शिखर पर पहुंचाया हो, विदेशों में हर जगह उनकी छवि विराट और उजली बन जायेगी, ऐसा नहीं है.

भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ता है, वह पिछले हजार बरस के भारतीय इतिहास से ही निकला है. इन रिश्तों का इतिहास जितना हमको खींचता है, उतना ही पाक को भी. दोनों के बीच युद्ध हुआ तो वह ऊपरी तौर से भले ही अंतरराष्ट्रीय युद्ध होगा, पर एक गहरे मायने में वह एक गृहयुद्ध भी होगा, जो सीमा के आर-पार दोनों देशों में अंधी अराजकता को कस्बों-गलियों में बिखरा देगा. इतिहास का पेंडुलम भारत में बहुत कम घूमा है. हमारे यहां ऐसे शस्त्रास्त्र थे, ऐसे उड़नखटोले और मिसाइलें थीं, इस तरह की अवैज्ञानिक सबूतविहीन बातों पर बोलने के व्यावहारिक नतीजे क्या हैं? विदेशी अखबारों की शंकाएं इनकी खिल्ली उड़ रही हैं.

आज अगर सचमुच युद्ध हुआ, तो उन पांच हजार साल पुराने युद्ध के नुस्खों को हम क्या साकार कर सकेंगे? इसका जवाब शायद सिर्फ रहस्यवाद के लेवल पर दिया जा सकता है. पर हथियारों की क्षमता, वाजिब कीमत या सेना की तैयारी से जुड़े वाजिब, व्यावहारिक सवालों को लेकर राजकीय असहिष्णुता हमारे राजनय की असफलता और एशिया में हमारा अकेलापन जताती है. क्या यह विडंबना नहीं कि जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निहत्थे नागरिकों को घर में घुसकर मारना नितांत संभव बनता जा रहा है? कश्मीर पर पिछले पांच बरसों में जुआ खेलते-खेलते 2019 में दांव कितने ऊंचे होते जा रहे हैं? और चुनावी खेल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीयत से अगर पड़ोस पर हमला कर दिया गया, तो वह भारत के विश्व हितों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? सरकार से जरूरी सवाल पूछना आखिर क्यों मना हो?

हमको याद रखना चाहिए कि भारत-पाक युद्ध छेड़ने-रोकने की चाभी न भारत के पास है, न पाक के पास. वह बीजिंग, वाशिंगटन, मास्को और सऊदी अरब के हाथ में है. जनसंपर्क और आत्म-प्रचार को हमारे नेतृत्व ने शुरुआती काल में चाहे जितना भी शिखर पर पहुंचाया हो, विदेशों में हर जगह उनकी छवि विराट और उजली बन जायेगी, ऐसा नहीं है. वैश्विक ताकत की बिसात पर अपने लिए जगह बनाते भारत को ऐसे दोस्त चाहिए, जिनसे उसके हित-स्वार्थों का मेल हो. हमारा भ्रम ही है कि दोस्तों की गरज सिर्फ पाक को है, हमको नहीं.

दुनिया के राजनय के अखाड़े में बड़ी ताकतें अंततः देश विशेष की दोस्ती की कीमत उतनी ही लगायेंगी, जितना वह भीतर से शक्तिशाली हो. इस समय जब विदेश की मुख्यधारा का मीडिया भारत को बार-बार सांप्रदायिक आग से झुलसते, बेरोजगारों और भ्रष्ट भगोड़ों वाला देश साबित करता हो, 108 शीर्ष अर्थशास्त्री खुद सरकार द्वारा अपने ही नकारात्मक आंकड़ों को झुठलाने पर चिंता जतायें, निवेशक हमको अपने सार्वजनिक बैंकों का दोहन करने का दोषी मानने लगें, उस समय उसकी तरफ दोस्तीभरे हाथ जरा कम ही बढ़ेंगे. चुनावों का क्या है, मई अंत तक सरकार तय हो ही जायेगी. लेकिन, इस समय युद्धोन्माद फैलाने की नादानी नयी सरकार को घरेलू तथा वैदेशिक, दोनो मोर्चों पर बहुत भारी पड़ेगी.

तमिलनाडु में कांटे का मुकाबला

आर राजागोपालन
वरिष्ठ पत्रकार
rajagopalan1951@gmail.com

तमिलनाडु का नाम आते ही आपके जेहन में जयललिता, एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) और करुणानिधि जैसे कद्दावर नेताओं की यादें ताजा हो जाती होंगी. वर्ष 2019 के आम चुनाव इस राज्य में ऐसे पहले चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अभियान से इस तिकड़ी में बाकी बचे दो नेता भी अनुपस्थित हैं. तमिलनाडु में 18 अप्रैल को होनेवाले मतदान में इस राज्य के मतदाता कुल 39 लोकसभा सदस्यों के चुनाव करेंगे. पड़ोस के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की एक सीट के लिए भी उसी दिन मतदान होंगे. इस बार के चुनाव अभियान में यहां के परंपरागत दो खेमों का नेतृत्व क्रमशः डीएमके से करुणानिधि के सुपुत्र एमके स्टालिन और एआइएडीएमके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी कर रहे हैं. एआइएडीएमके का डॉ रामदोस की पार्टी पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), विजयकांत की देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) एवं भाजपा के साथ गठबंधन है. जातियों की दृष्टि से देखने पर यह गठबंधन शक्तिशाली है. दूसरी ओर डीएमके का कांग्रेस, सीपीआइ एवं मुसलिम लीग के साथ गठबंधन है, और इसकी भी पूरे राज्य में दमदार मौजूदगी है.

तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए इस राज्य में जाति तथा धर्म के प्रभाव को जानना जरूरी है. यहां थेवर, नडार, वन्निआर तथा गोंडर सर्वाधिक शक्तिशाली जातियां हैं. इस हिसाब से एआइएडीएमके ने इस संतुलन को अधिक बेहतर तरीके से थाम रखा है. उधर डीएमके की भी अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच अच्छी राज्यव्यापी पैठ है. स्टालिन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है, तो उधर एआइएडीएमके इस पद के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही है. इससे इन दो खेमों को क्रमशः राहुल और मोदी के समर्थकों का साथ भी मिल जा रहा है. जैसे-जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, इन दोनों खेमों के बीच मुकाबला और भी कठिन होता जा रहा है.

तमिलनाडु की राजनीति पर सिने सितारों का भी खासा वर्चस्व रहा है. एमजीआर तथा जयललिता ने अपने कदम सिनेमा जगत से ही सियासत में रखे थे. करुणानिधि ने भी नाटककार तथा नाटकों में अभिनेता, फिल्मों के पटकथा एवं संवाद लेखक तथा गीतकार के रूप में अभिनय एवं सिनेमा के माध्यमों द्वारा अपनी प्रारंभिक लोकप्रियता संवारी थी. यहां आज भी सिनेमा से लोकप्रिय हुई शख्सीयतों का असर बदस्तूर कायम है. हालांकि, दक्षिण में व्यापक रूप से लोकप्रिय सिनेमा सितारे रजनीकांत इन आम चुनावों में भाग नहीं ले रहे हैं, पर कमल हासन इस अभियान में मौजूद हैं और उनकी पार्टी मक्कल निधि मैयम के उम्मीदवार तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे अनुमान किये गये हैं कि इनमें से लगभग प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कमल हासन के औसतन 20 हजार मत सुरक्षित हैं, जिनके बल पर उनके उम्मीदवार जीते या नहीं, वे दूसरे उम्मीदवारों की मांद में सेंध लगाने में तो अवश्य ही सफल रहेंगे. ऐसा समझा जाता है कि इससे मुख्य हानि एआइएडीएमके उम्मीदवारों को पहुंचेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ डीएमके उमीदवारों को मिलेगा.

सियासी रुझानों के मुताबिक एआइएडीएमके तथा डीएमके दोनों को 50-50 प्रतिशत सीटें दी जा रही हैं, पर चुनावी सर्वेक्षणों ने डीएमके को अधिक सीटों का फायदा मिलता बताया है.

जयललिता के निधन के बाद उनकी पार्टी में वर्चस्व के लिए चले आंतरिक संघर्ष के दौर में मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के नेतृत्व को टीटीवी दिनाकरन ने चुनौती दी और फिर अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के नाम से एक नयी सियासी पार्टी की स्थापना की. दिनाकरन की इस पार्टी के उम्मीदवार भी इन राज्यों के सभी 40 सीटों से ये चुनाव लड़ रहे हैं और वे एआइएडीएमके उम्मीदवारों के ही वोट काटेंगे. राज्य में जयललिता के कट्टर समर्थक कार्यकर्ताओं की खासी तादाद अब भी मानती है कि दिनाकरन की यह पार्टी ही जयललिता की विरासत की असली हकदार है, इसलिए वह इन उम्मीदवारों के साथ खड़ी है. अतः एआइएडीएमके उम्मीदवारों को यह नुकसान भी झेलना ही होगा.

सियासी रुझानों के मुताबिक एआइएडीएमके तथा डीएमके दोनों को 50-50 प्रतिशत सीटें दी जा रही हैं, पर चुनावी सर्वेक्षणों ने डीएमके को अधिक सीटों का फायदा मिलता बताया है. राज्य में एआइएडीएमके की सरकार प्रधानमंत्री मोदी तथा केंद्र के समर्थन पर टिकी है. क्या मोदी की लोकप्रियता का लाभ भी एआइएडीएमके को मिल सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक ही है, क्योंकि यहां पहली बार मत दे रहे युवा मतदाताओं में नरेंद्र मोदी खासे लोकप्रिय हैं. ये युवा दस वर्षों के यूपीए शासनकाल में भ्रष्टाचार तथा घोटालों के दौर से वाकिफ हैं और उनके लिए यह एक प्रमुख मुद्दा है.

दूसरी ओर, यह भी सत्य है कि राजीव गांधी के साथ राहुल तथा प्रियंका से सहानुभूति रखनेवाले अपनी जगह कायम हैं, क्योंकि तमिलनाडु ही राजीव गांधी की निधन स्थली है. राहुल और प्रियंका जब भी तमिलनाडु के दौरे पर आते हैं, तो वे पिता को श्रद्धांजलि देने श्रीपेरुंबुदूर अवश्य जाया करते हैं. स्थानीय मुद्दों के रूप में पानी, आवास, सड़कों की समस्याओं की अहमियत भी अपनी भूमिका निभायेगी. राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में पानी का संकट बरकरार है, जो गर्मी में और गहरा होगा. पर चूंकि ये चुनाव उसके पूर्व ही संपन्न हो जायेंगे, सो सत्तारूढ़ पार्टी उसके दंश से बच निकलेगी.

(अनुवाद: विजय नंदन)

बोधि वृक्ष

पालन करें

हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक छोटा अंश है. पृथ्वी सौर मंडल के एक कोने में है और सूर्य की परिक्रमा कर शक्ति संग्रह करती है. इसलिए इस पृथ्वी पर रहनेवाले प्रत्येक जीव पर स्वभाविक रूप से ग्रह-नक्षत्र का गहरा प्रभाव पड़ता है. प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को शनिचरा ग्रह लगा हुआ है या शनि की साढ़ेसाती लगी हुई है. इसका अर्थ है कि सौर मंडल का एक प्रभावशाली ग्रह शनि पृथ्वी के मनुष्य को प्रभावित कर रहा है. यह खोज हमारे ऋषि-मुनियों की है. हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक अंश है. शास्त्रों में कहा गया है कि यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है. जिन तत्वों से शरीर बना है, उन्हीं तत्वों से पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, ग्रह-नक्षत्र भी बने हैं. विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के केंद्र में मैग्नेटिक और फेरस ऑक्साइड है, जिसके कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण है. इसका सीधा अर्थ यह है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति की वजह से मनुष्य का शरीर प्रतिक्षण प्रभावित होता रहता है. इस दृष्टि से मनुष्य सीधे सूर्य से प्रभाव ग्रहण करता है. हम जो सांस लेते हैं, वह ऑक्सीजन हमें परोक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा लेकर ही पेड़-पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं. यह प्रवचन नहीं है, तथ्य है. इसको अच्छी तरह समझें. हम अक्सर वेद, उपनिषद् पढ़ते है, मनीषियों और संतों के प्रवचन सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन पर उनका सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? इसका कारण यह है कि हमारे जीवन का लेंस इतना संवेदनशील है कि हमारे सामने जो भी दृश्य आते है, वह तुरंत उसे ग्रहण कर लेता है. हमारे मस्तिष्क पर बननेवाला वर्तमान चित्र स्थायी हो जाता है, लेकिन उसके पहले के सभी चित्र गौण हो जाते हैं. जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं और प्रवचन सुनते हैं, तो उस क्षण तो हम उन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, लेकिन जैसे ही उस जगह से हटते हैं, तो सांसारिकता फिर से हमारे चारों ओर खड़ी हो जाती है. कहने का अर्थ है कि हम अपने शरीर को भलिभांति जानें और प्रवचन को केवल सुने ही नहीं, उसका पालन भी करें.

आचार्य सुदर्शन

आपके पत्र

मतदान पर्ची का मिलान कराने की मांग

हैरत नहीं होगी, जब कुछ दिनों बाद राजनीतिक दल यह मांग करने लगेंगे कि शत प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान इवीएम से किया जाये. कुछ दल इवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग कर रहे हैं. यह कुछ वैसी ही विचित्र मांग है, जैसे कोई ट्रेन दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बैलगाड़ी से यात्रा को बेहतर बताये. 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान इवीएम से करने की मांग इसलिए अनावश्यक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग करीब-करीब हर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ की मतदान पर्चियों का मिलान करता है. अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी है. आखिर जब इस व्यवस्था में कोई विसंगति नहीं मिली, तब फिर 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों के मिलान की मांग का क्या मतलब? यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट को याचिकाओं का निपटारा करना ही होता है, लेकिन उसे याचिकाकर्ता का मूल मकसद देखना ही चाहिए.

डॉ हेमंत कुमार, भागलपुर

अब भाजपा की बारी !

कांग्रेस का शानदार लोकलुभावन घोषणा पत्र तो आ ही गया है, जिसमें 22 लाख सरकारी नौकरियां, 72 हजार रुपये वर्ष में हर गरीब परिवार को दिये जायेंगे, किसानों का अलग से बजट और कर्ज न चुका पाने पर फौजदारी केस नहीं आदि ढेर सारे वायदे किये हैं. इसको लेकर भाजपा हमलावर हो चुकी है और उसकी कमियां निकालने में जुट गयी है. अब भाजपा के घोषणापत्र की बारी है. यदि वह चाहे तो इससे भी अच्छा घोषणा पत्र दे कर आगे निकल सकती है. इसमें वह और भी बड़े रोजगार को जनसंख्या नियंत्रण से ठोस तरीके से जोड़ कर कांग्रेस से बहुत आगे निकल सकती है क्योंकि उसके घोषणापत्र में यह सब नहीं है. पार्टियां प्रायः ढेर सारे वायदे तो जरूर करती हैं, मगर उनकी असलियत भी किसी से छुपी नहीं है. यदि पार्टी चाहे तो इन्हें पूरा करके ही अपनी स्थायी साख भी बना सकती है.

वेद मामूरपुर, नरेला

अल्पाहार से भी हो रही मौत

चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नये शोध पर प्रतिवेदन प्रकाशित करने वाले सबसे विश्वसनीय एवं सबसे पुरानी पत्रिका है लैंसेट. यह वर्ष 1823 से ही प्रकाशित हो रहा है. इसके ताजा अंक में आहार यानी भोजन को लेकर शोध रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार सिर्फ कुपोषण से ही नहीं बल्कि अल्पाहार से भी दुनिया भर में अच्छी खासी मौतें हो रहीं हैं. अध्ययन का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर, हर साल पांच मौतों में से एक यानी एक करोड़ 10 लाख मौतें आहार से जुड़ी है. रिपोर्ट में प्रकाशित सूची में भारत का स्थान 118वां है. इस्राइल में सबसे कम यानी 89 मौतें प्रति लाख आबादी पर और सबसे ज्यादा 892 मौतें प्रति लाख उज्बेकिस्तान में हो रहा है. भारत में 310 मौतें भोजन की कमी या गलत भोजन के कारण हो रहा है. क्या लोगों को चटकारा वाले भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाएगी?

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी ,जमशेदपुर

कुछ अलग

खुशामद कर बुलंद इतनी

सुरेश कांत
वरिष्ठ व्यंग्यकार
drsureshkant@gmail.com

'मार्च' का शाब्दिक अर्थ भले ही शुरू करना, कूच करना, प्रयाण करना हो, पर हकीकत में उसका ताल्लुक रुकने, खत्म करने, बंद करने से है, जिसे 'क्लोजिंग' भी कहते हैं. सरकार का साल अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होता है. जरूर इसके पीछे कोई राज होगा, जिसे सरकार ही जानती होगी, पर उसे सार्वजनिक करना शायद सुरक्षा-हितों के खिलाफ होगा. 'एकोऽहं' सरकार अनेक दफ्तरों के रूप में 'बहुस्याम' होती है. निराकार सरकार के इन दफ्तरों में साकार विराजते हैं दफ्तरों को सुशोभित करनेवाले हर प्रकार के उसके बंदे. जिस प्रकार पंचतत्वों से मानव-शरीर निर्मित होता है, उसी प्रकार दफ्तरों के निर्माण में भी पांच परम शक्तियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं- साहब, अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टेनो और चपरासी. इनमें से साहब साहब होता है, बाकी उसके बंदे. कबीर ने ठीक ही लिखा है- साहब सों सब होत है बंदे ते कछु नाहिं! बंदों की सरफरोशी, बिना उनके यह गाये भी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कब हो जाये, कहा नहीं जा सकता.

साहब सेमिनार बुलाता है, साहब कांफ्रेंस करता है, साहब कोर ग्रुप बनाता है. साहब की संस्तुति के बाद ही बंदे फील्ड में जाते हैं. फील्ड में जानेवाले फील्ड में ही भटकते रहते हैं. असली लाभ तो उनको मिलता है, जो हेडक्वॉर्टर में ही जमे रहते हैं. पूजा वही जाता है, जो साहब के चक्कर लगाता है. इस दुनियादारी का बोध सबसे पहले गणेश जी को हुआ था, जिन्होंने दुनिया का चक्कर माता-पिता की परिक्रमा करके ही लगा लिया था. साहब की भी परिक्रमा लगाती रहनी पड़ती है बंदों को, उनकी नजरों के सामने बने रहना होता है. बंदे को घर-बार यानी घर और बाहर दोनों चलाना पड़ता है अपने साहब का. साहब खुश, तो बंदे का भी कारोबार चलता रहता है. यह तो सर्वविदित है कि आजकल ब्रांडेड से ज्यादा असेंबल्ड की पूछ होती है.

फील्ड में जानेवाला स्टाफ फील्ड में भी शिकार कर लेता है, पर तभी तक, जब तक साहब चाहें. साहब को जैसे ही आभास होता है कि फील्ड में वर्षा हो रही है, खासकर धन की, तो स्टाफ को वापस बुला लेता है. साहब को गच्चा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वे तो कच्चा खा जाते हैं. साहब की शक्ति-पूजा 'जी सर', 'यस सर', 'एक्सक्यूज मी सर', 'पार्डन सर' और 'थैंक्यू सर' जैसे मंत्रों से की जाती है.

साहब का असली रुआब मार्च में ही देखने को मिलता है. मार्च यानी बंदों की गति, प्रगति, सद्गति या अधोगति का संभावित माह. दुर्गति को प्राप्त नहीं होते वे, जो साहब को देखते ही 'शोभित कर नवनीत लिए' की मुद्रा धारण कर लेते हैं. बापू ने भी दांडी मार्च के लिए मार्च महीना तय किया था. सोचिए, अगर वे कोई और महीना चुनते, तो उसे 'दांडी मार्च' कहना मुश्किल हो जाता. मातहतों को भी मार्च में ही दांडी-मार्च करना होता है, अपनी सीआर लिखवानी होती है साहब से, जिसके लिए कहा गया है- खुशामद कर बुलंद इतनी कि हर सीआर से पहले, साहब बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है?

देश दुनिया से

अफगानिस्तान में शांति बहाली के प्रयास

अफगानिस्तान में पिछले महीने सभी जातीय और भाषायी समूह की लगभग 3,500 महिलाओं ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर देश में ऐसी शांति बहाली की मांग की थी, जिसमें महिलाओं को फिर से तालिबानी युग की भयावहता का सामना न करना पड़े. अफगान सरकार भी शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसी शांति चाहती है, जो गणतंत्र के मूल्यों और अफगानी लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को सुदृढ़ करे, न कि जो राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हो. अफगान सरकार के इस गंभीर समस्या को हल करने के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप, अफगानिस्तान के दशकों पुराने संघर्ष के शांतिपूर्ण, स्थायी समाधान के लिए फिर से उम्मीद जगी है. शांति स्थापना के लिए हजारों अफगानों ने अपना जीवन बलिदान किया है. लेकिन चार दशकों से संघर्षरत देश में स्थायी शांति लाने के लिए ये बलिदान ही पर्याप्त नहीं हैं. अफगानिस्तान को शांति के लिए अब सही रणनीति और व्यावहारिक नेतृत्व की आवश्यकता है, ताकि शांति की राह में बची आखिरी बाधा भी वहां से दूर हो सके. शुक्र है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में स्थायी शांति बहाली के लिए एक व्यापक और व्यावहारिक रणनीति तैयार की है.

शमीम आरिफ

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है